(e) what steps have been taken to see that the closed units start functioning before long?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (e). The required information is being collected from the Government of U.P. and will be laid on the Table of the House.

राज्य व्यापार निगम

*703. **श्री शारदा नन्द :**
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री टी० पी० शाह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के कार्य संचालन के बारे में कभी जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य व्यापार निगम ठीक तरह से कार्य करती रहे, इसके लिये पिछले एक वर्ष में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) गत छः महीनों में राज्य व्यापार निगम से कितने अधिकारियों का तबादला किया गया है और उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) उनके तबादले के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) . अप्रैल, 1968 में सरकार ने राज्य व्यापार निगम की व्यापारिक तकनीकों तथा पद्धतियों और इसके वर्तमान संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है जिससे उसकी कार्य-दक्षता को और भी सुदृढ़ बनाने और सुधारने के लिए अपेक्षित उपाय किये जा सकें। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ.) : निम्नलिखित चार अधिकारियों को, उनके कार्यकाल की समाप्ति पर, उनके मूल विभागों में वापिस भेज दिया गया :—

1. श्री पी० के० सेशन, प्रभागीय प्रबन्धक
2. श्री एन० एल० सहदेव, प्रभागीय प्रबन्धक
3. श्री डी० एन० नंदी, उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक
4. श्री एस० एस० गुलाटी, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक

श्री बी० पी० पटेल तथा श्री जी० एस० स्याल ने अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर क्रमशः अध्यक्ष तथा निदेशक के अपने पदों का कार्यभार छोड़ दिया।

CENTRAL ORGANISATION FOR FOREIGN PROCESSES AND KNOW-HOW

*705. SHRI CHENGALARAYA NAIDU :
SHRI D. N. PATODIA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to create a Central Organization to look after the purchases of foreign processes and know-how ;

(b) if so, the purpose of the said organization ;

(c) whether the organisation will help the Foreign Investment Board, recently set up by Government, to regulate the foreign collaboration; and

(d) whether the various Ministries are opposed to the organization because this will curtail their powers ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). The Government are considering the feasibility of procuring know-how and technology on a centralised basis in respect of certain manufacturing sectors and processes. The object of such centralised

procurement, wherever this is found practicable, is to avoid repetitive purchase of such know-how through different parties, involving heavy foreign exchange liabilities, and to encourage indigenous research and technological development. The question of utilisation of various existing agencies for this purpose is under consideration. It may not be practicable for any one organisation to procure, assimilate and transmit to others technological know-how in various specialised fields of industry.

(d) Does not arise.

AGREEMENT WITH EUROPEAN COMMON MARKET COUNTRIES

*706. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the arrangements arrived at with the European Common Market countries for giving facilities to India on items other than on handloom, cotton and silk fabrics;

(b) the nature of facilities being given by them;

(c) the value of Indian goods likely to be exported to the European Common Market and the advantages expected to be accrued to India therefrom; and

(d) the further prospects of any increase in such exports?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT*—1931/68.]

दिल्ली में स्थापित नये उद्योग

*707. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत दो वर्षों में कितने नये उद्योग स्थापित किये गये हैं तथा सरकार ने उन्हें किस प्रकार की सहायता दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक उद्योग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहां पर सरकार की ओर से उद्योगों को कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को दिल्ली उद्योगपतियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) गत दो वर्षों में दिल्ली में 3 बड़े और 182 छोटे कारखाने स्थापित किए गये हैं। सरकार आयातित कच्चे माल, पुर्जा, फालतू पुर्जा व दुर्लभ माल प्राप्त करने में सहायता देती है। छोटे कारखानों को दी जाने वाली सहायता के अधीन किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत मशीनों की खरीद दिल्ली वित्त निगम से ऋण, कुटीर एवं लघु उद्योगों निगम से राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण तथा उद्योगों को दूसरे स्थानों पर लेके जाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन खरीदने। कारखाने बनाने के लिए ऋण की सुविधाएं भी सम्मिलित हैं।

(ख) 1966 से पूर्व स्थापित बड़े क्षेत्र के केवल तीन कारखानों ने अपना स्थान दिल्ली से फरीदाबाद बदलने के लिए सरकार से अनुमति मांगी क्योंकि उन्हें और बड़े स्थान की आवश्यकता थी। अपना स्थान बदलने के लिए उन सबको अनुमति दे दी गयी है। किसी छोटे कारखाने द्वारा स्थान बदलेजाने के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ). जमीन प्राप्त करने में कठिनाइयों तथा जमीन व कच्चे माल की ऊंची कीमतों के बारे में दिल्ली